The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 2 | February 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

बिहार के बांका जिले में शिक्षित युवाओं के प्रवासन व्यवहार पर सरकारी स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं का प्रभाव: एक अनुभवजन्य विश्लेषण

दिव्यांशु कुमार मिश्रा

शोधार्थी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18975538

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-02-2026

Published: 10-03-2026

Keywords:

प्रवासन, बांका, कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, कौशल-बेमेल, काई-स्क्वायर परीक्षण, जनसांख्यिकीय लाभांश, आकांक्षी प्रवासन।

ABSTRACT

विकास अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी के समकालीन विमर्श में, बिहार राज्य एक विशिष्ट केस स्टडी प्रस्तुत करता है, जहाँ प्रचुर मानव संसाधन और सीमित औद्योगिक ढांचे के बीच एक संरचनात्मक असंतुलन विद्यमान है। यह शोध पत्र बिहार के 'आकांक्षी जिले' (Aspirational District) बांका के विशेष संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा समर्थित कौशल विकास (जैसे कुशल युवा कार्यक्रम - KYP) और स्वरोजगार (जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना - MMUY) योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है। ऐतिहासिक रूप से, बिहार से प्रवासन की प्रवृत्ति 'संकटग्रस्त' (Distress Migration) रही है, जो ग्रामीण गरीबी और रोजगार के अभाव से प्रेरित रही है। हालाँकि, हाल के आंकड़े, विशेष रूप से बांका जिले में पासपोर्ट आवेदनों की अभूतपूर्व वृद्धि, 'आकांक्षी प्रवासन' (Aspirational Migration) की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रतिमान बदलाव (Paradigm Shift) का संकेत देते हैं। इस अध्ययन में 300 उत्तरदाताओं के प्राथमिक आंकड़ों (काल्पनिक) का उपयोग करते हुए, काई-स्क्वायर (Chi-Square) सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है कि क्या कौशल उन्नयन ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया है या अनजाने में बाहरी प्रवासन को सरल बनाया है। परिणाम यह बताते हैं कि जबकि 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' ने पूंजी के स्वामित्व के माध्यम से प्रवासन को रोकने में सकारात्मक योगदान दिया है,

केवल 'कौशल विकास' (स्थानीय औद्योगिक अवशोषण के बिना) ने 'कौशल-बेमेल' (Skill Mismatch) की स्थिति को उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित युवाओं में राज्य से बाहर जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह शोध पत्र नीतिगत हस्तक्षेपों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि 'न्यू एज इकोनॉमी' (New Age Economy) के लक्ष्यों के अनुरूप जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग किया जा सके।

1. प्रस्तावना (Introduction)

1.1 अनुसंधान की पृष्ठभूमि एवं महत्व

बिहार, भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित, देश की जनसंख्यात्मक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2011 की जनगणना और हालिया आर्थिक अध्ययनों के अनुसार, बिहार भारत का सबसे युवा राज्य है, जहाँ लगभग 58% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। यह बड़ा युवा वर्ग एक ओर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) का अवसर पेश करता है, तो वहीं, यदि उन्हें उत्पादक रोजगार नहीं दिया गया, तो यह 'जनसांख्यिकीय आपदा' में बदल सकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, राज्य ने 15.5% की जीएसडीपी (GSDP) वृद्धि दर दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और राज्य सरकार 'न्यू एज इकोनॉमी' के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

हालांकि, आर्थिक विकास के इन आंकड़ों के बावजूद, श्रम बाजार की संरचनात्मक समस्याएं अभी भी उपस्थित हैं। बिहार की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 43.4% है, जो राष्ट्रीय औसत 56.0% से काफी कम है। खासतौर पर बांका जिला, जो झारखंड की सीमा से सटा हुआ एक आदिवासी बहुल और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्र है, विकास के विभिन्न मानकों पर पीछे है। नीति आयोग ने इसे 'आकांक्षी जिला' माना है, जो इसके सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार की तात्कालिक आवश्यकताको दर्शाता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से, बांका जैसे क्षेत्रों से प्रवासन एक जीवित रहने की रणनीति है। प्रो. अलख एन. शर्मा और जेरी रोजर्स के दीर्घकालिक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन का प्रमुख कारण कृषि में कम उत्पादकता और गैर-कृषि रोजगार की कमी रही है। पिछले दहाई में, राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए **'सात निश्चय' के अंतर्गत 'कुशल युवा कार्यक्रम' (KYP) और 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना'**

(MMUY) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य युवाओं को कौशल और पूंजी प्रदान कर उन्हें 'नौकरी खोजने वाले' (Job Seekers) के बजाय 'नौकरी देने वाले' (Job Creators) में बदलना था।

1.2 समस्या कथन (Problem Statement)

इस शोध का मुख्य प्रश्न एक विरोधाभास (Paradox) से सामने आता है। सैद्धांतिक रूप से, कौशल विकास और स्व-रोजगार योजनाओं को स्थानीय स्तर पर आय के अवसर बढ़ाकर प्रवासन को कम करना चाहिए। लेकिन, बांका जिले का अनुभवात्मक प्रमाण एक अलग कहानी प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, बांका जिले में पासपोर्ट जारी करने की दर में वृद्धि हुई है, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। यह तथ्यात्मक सबूत संकेत करता है कि कौशल और शिक्षा प्राप्त करने के बाद, बांका के युवा स्थानीय अर्थव्यवस्था में रुकने के बजाय, वैश्विक और राष्ट्रीय श्रम बाजारों में बेहतर अवसरों की खोज में पलायन करने के लिए अधिक इच्छुक हैं।

क्या सरकारी योजनाएं, खासकर कौशल विकास, अनजाने में प्रवासन को बढ़ावा दे रही हैं? क्या स्थानीय उद्योगों की आधारभूत संरचना की कमी के चलते प्रशिक्षित युवाओं में 'कौशल-बेमेल' (Skill Mismatch) की समस्या पैदा हो रही है? यह शोध पत्र इन सवालों की विस्तृत जांच करता है।

1.3 शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. **प्रवासन की प्रकृति का विश्लेषण:** बांका जिले के शिक्षित युवाओं के प्रवासन व्यवहार (संकटग्रस्त बनाम आकांक्षी) में परिवर्तन का अध्ययन करना।
2. **योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन:** 'कुशल युवा कार्यक्रम' (KYP) और 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' (MMUY) के लाभार्थियों और गैर-लाभार्थियों के बीच प्रवासन प्रवृत्ति में भेद का सांख्यिकीय परीक्षण करना।
3. **कौशल-बेमेल की जांच:**
   यह पहचानना कि क्या उपार्जित कौशल और क्षेत्रीय नौकरी के अवसरों में कोई अंतर है जो प्रवासन को उत्तेजित करता है।
4. **नीतिगत सुझाव:**
   बांका जिले की विशेष परिस्थितियों में, प्रवासन के प्रबंधन तथा स्थानीय रोजगार निर्माण के लिए साक्ष्य-आधारित नीतिगत जलवायु प्रदान करना।

1.4 परिकल्पना (Hypothesis)

शोध के लक्ष्यों के अनुसार, निम्नलिखित सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाएगा:

$H_0$1 (शून्य परिकल्पना): सरकार की योजनाओं (KYP/MMUY) का उपयोग करने और शिक्षित युवाओं के प्रवासन के व्यवहार के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध (Significant Association) नहीं है।

$H_1$1 (वैकल्पिक परिकल्पना): सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और शिक्षित युवाओं के पलायन के बीच महत्वपूर्ण सांख्यिकी संबंध पाया जाता है।

2. साहित्य अवलोकन (Literature Review)

2.1 प्रवासन के सिद्धांत: शास्त्रीय से समकालीन तक

प्रवासन का अर्थशास्त्र 'पुश और पुल' कारकों के बीच की प्रतियोगिता पर निर्भर करता है। एवरेट ली का सिद्धांत इंगित करता है कि उद्गम स्थल की नकारात्मक परिस्थितियाँ (पुश) और गंतव्य स्थल की सकारात्मक परिस्थितियाँ (पुल) प्रवासन को प्रेरित करती हैं। हैरिस-टोडारो मॉडल इसे और समझाता है, यह बताते हुए कि प्रवासन का निर्णय अपेक्षित आय (Expected Income) के अंतर पर आधारित होता है, न केवल वर्तमान आय पर।

बिहार के संदर्भ में,

अलख एन। शर्मा (2005, 2024) और जेरी रोजर्स (2016) के अनुदैर्ध्य अध्ययनों से पता चला है कि बिहार से प्रवासन का स्वरूप बदल रहा है। पहले यह केवल भूमिहीन मजदूरों तक सीमित था, लेकिन अब यह मध्यम और उच्च जातियों के शिक्षित युवाओं में भी बढ़ गया है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर जीवनशैली की खोज में पलायन कर रहे हैं। शर्मा (2024) ने हाल ही में बताया है कि शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी की ऊँची दर (शहरी बिहार में 10.8%) उन्हें प्रवासन के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि स्थानीय बाजार में उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

2.2 कौशल विकास और रोजगार का अंतर्संबंध

मानव पूंजी सिद्धांत के (Human Capital Theory) अनुसार, शिक्षा और प्रशिक्षण से किसी व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होती है। हालांकि, अगर स्थानीय अर्थव्यवस्था इस बढ़ी हुई उत्पादकता को अपनाने में असमर्थ

है, तो यह 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) का कारण बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन **(ILO)** और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट **(IHD)** की **'भारत रोजगार रिपोर्ट 2024'** यह दर्शाती है कि भारत में, खासकर बिहार जैसे राज्यों में, 'कौशल बेमेल' (Skill Mismatch) एक महत्वपूर्ण समस्या है। रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी डिग्रीधारी युवाओं में बेरोजगारी की दर अशिक्षित युवाओं की तुलना में अधिक है, जो यह इंगित करता है कि शिक्षा प्रणाली और बाजार की जरूरतों में सामंजस्य नहीं है।

2.3 सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन

कुशल युवा कार्यक्रम (KYP): अध्ययनों से संकेत मिलता है कि KYP ने युवाओं में सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया है। किन्तु, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट बांका समेत कई जिलों में केंद्रों के संचालन में असमानताओं और प्लेसमेंट लिंक की कमी को उजागर करती है। प्लेसमेंट के अभाव में, यह प्रशिक्षण युवाओं को स्थानीय कृषि कार्यों के लिए 'अयोग्य' और बाहरी शहरी नौकरियों के लिए 'आकांक्षी' बनाता है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (MMUY): इसके विपरीत, उद्यमिता योजनाओं का प्रभाव अधिक सकारात्मक रूप से देखा गया है। एक शोध के अनुसार, इस योजना ने बिहार में, विशेषकर EBC (42%) और SC/ST (31%) समुदायों में, उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। जब युवाओं को पूंजी (10 लाख रुपये तक) मिलती है, तो वे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके स्वयं का रोजगार उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रवास की संभावना घट जाती है।

3. शोध प्रविधि (Research Methodology)

इस अध्ययन में मात्रात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण (Quantitative Research Approach) अपनाया गया है, जो प्राथमिक आंकड़ों के अनुभवजन्य विश्लेषण पर आधारित है।

3.1 अध्ययन क्षेत्र: बांका जिला

बांका का चयन इसके अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल के कारण किया गया है। यह एक 'आकांक्षी जिला' है, जहाँ साक्षरता दर (58.17%) कम है, लेकिन हाल के वर्षों में विकास की तेज गति देखी गई है। ओढ़नी डैम और मंदार पर्वत जैसे पर्यटन स्थलों के विकास ने यहां नई रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी पासपोर्ट आवेदनों में वृद्धि एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है।

3.2 नमूनाकरण विधि (Sampling Design)

जनसंख्या: बांका जिले के शिक्षित युवा (18-35 वर्ष, न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण)।

नमूना आकार (Sample Size): 300 प्रतिभागी।

नमूना विधि: बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (Multi-stage Stratified Random Sampling)।

पहले स्तर: बांका जिले के तीन प्रखंडों का चुनाव - बांका सदर (शहरी/अर्ध-शहरी), अमरपुर (कृषि केंद्रित), और कटोरिया (आदिवासी/वन क्षेत्र)।

द्वितीय स्तर: हर प्रखंड से 100 उत्तरदाताओं का चुनाव, जिसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और गैर-लाभार्थी दोनों शामिल हैं।

3.3 डेटा संग्रह उपकरण

एक सुविस्तृत प्रश्नावली (Structured Questionnaire) का उपयोग किया गया, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल थे:

1. सामाजिक-आर्थिक पहचान (उम्र, समुदाय, अध्ययन)।
2. योजना की जानकारी (KYP, MMUY, BSCC आदि के लाभ)।
3. प्रवासन की स्थिति (क्या आप कभी प्रवासित हुए हैं या ऐसा करने का सोच रहे हैं?)।
4. प्रवासन के कारण (धकेलने वाले/खींचने वाले तत्व)।

3.4 सांख्यिकीय उपकरण

एकत्रित आंकड़ों को SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) का उपयोग करके कोडित और विश्लेषित किया गया। परिकल्पना परीक्षण के लिए **काई-स्क्वायर परीक्षण (Pearson's Chi-Square Test of Independence)** का उपयोग किया गया। यह परीक्षण दो श्रेणीबद्ध चरों (Categorical Variables) - 'योजना का प्रकार' और 'प्रवासन व्यवहार' - के बीच स्वतंत्रता की जांच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

4. बांका जिले की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और योजना परिदृश्य

4.1 जनसांख्यिकीय और आर्थिक संदर्भ

बांका जिला, जो अंग क्षेत्र में स्थित है, ऐतिहासिक रूप से कृषि और लघु कुटीर उद्योगों (जैसे तसर रेशम) पर निर्भर करता आया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, जिले का लिंगानुपात 907 है और शहरीकरण का स्तर बहुत ही कम है। एमएसएमई (MSME) विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएँ हैं, लेकिन बिजली की अनियमित आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की कमी एक बाधा के रूप में उपस्थित है।

4.2 योजनाओं का कार्यान्वयन

कुशल युवा कार्यक्रम (KYP): बांका में KYP केंद्र विस्तारित रूप से हैं। इनका लक्ष्य 15-28 वर्ष के युवाओं को हिंदी/अंग्रेजी संवाद और कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करना है। हालांकि, स्थानीय उद्योगों की कमी के कारण, यह कौशल युवाओं को कॉल सेंटर या डेटा एंट्री नौकरियों के लिए तैयार करता है, जो मुख्य रूप से बड़े शहरों में उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (MMUY): यह योजना 2018 में आरंभ की गई थी और 2021 में इसे महिलाओं और युवाओं के लिए विस्तारित किया गया। बांका में, इसका उपयोग कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों और छोटे निर्माण कार्यों के लिए किया गया है। सफल केस स्टडीज दर्शाती हैं कि जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया, उन्होंने न केवल अपने पलायन को रोका, बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान किया।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC): यह योजना उन्नत शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बांका में इसका कार्यान्वयन सफल रहा है, जिससे उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हुई है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC): यह योजना उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करती है। बांका में इसका कार्यान्वयन सफल रहा है, जिससे उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है ।

5. आंकड़ा विश्लेषण और व्याख्या (Data Analysis and Interpretation)

इस खंड में 300 उत्तरदाताओं से प्राप्त (काल्पनिक) प्राथमिक आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

5.1 उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वितरण

तालिका 1: उत्तरदाताओं का सामाजिक और शैक्षिक प्रोफाइल

विशेषता	श्रेणी	आवृत्ति (Frequency)	प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	195	65.0

विशेषता	श्रेणी	आवृत्ति (Frequency)	प्रतिशत (%)
	महिला	105	35.0
शिक्षा स्तर	इंटरमीडिएट (12वीं)	120	40.0
	स्नातक (Graduate)	140	46.7
	स्नातकोत्तर/तकनीकी	40	13.3
सामाजिक वर्ग	सामान्य (Gen)	45	15.0
	पिछड़ा वर्ग (OBC/EBC)	180	60.0
	एससी/एसटी (SC/ST)	75	25.0
कुल		**300**	**100.0**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा

विश्लेषण: तालिका 1 दर्शाती है कि बांका के शिक्षित युवाओं में ओबीसी (EBC सहित) का बाहुल्य (60%) है। यह बिहार सरकार की EBC-केंद्रित नीतियों, जैसे MMUY में विशेष प्रावधान, की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। महिलाओं का प्रतिशत (35%) कम है, जो राज्य में कम महिला श्रम भागीदारी (15.6%) को प्रतिबिंबित करता है ।

5.2 प्रवासन मंशा और योजना का अंतर्संबंध (Chi-Square Analysis)

यह अध्ययन का मुख्य भाग है, जहाँ हम यह जांचते हैं कि क्या किसी विशिष्ट सरकारी योजना का लाभार्थी होना प्रवासन की इच्छा को प्रभावित करता है।

तालिका 2: योजना प्रकार और प्रवासन व्यवहार (Cross-tabulation)

योजना की स्थिति	प्रवासन के लिए इच्छुक (हां)	स्थानीय रोजगार/स्वरोजगार (नहीं)	कुल (Total)
KYP लाभार्थी (कौशल विकास)	85 (77.3%)	25 (22.7%)	110
MMUY लाभार्थी (स्वरोजगार)	12 (24.0%)	38 (76.0%)	50
गैर-लाभार्थी (None)	83 (59.3%)	57 (40.7%)	140
कुल	**180**	**120**	**300**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा

प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा (300 उत्तरदाताओं) के आधार पर किए गए इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह जाँचना था कि क्या किसी विशेष सरकारी योजना (जैसे KYP या MMUY) का लाभ उठाने और व्यक्ति के प्रवासन (Migration) के प्रति रुझान के बीच कोई सार्थक सांख्यिकीय संबंध है।

वर्णनात्मक आँकड़ों (Descriptive Statistics) को देखने पर स्पष्ट रूप से दो विपरीत प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आती हैं। एक तरफ, कौशल विकास योजना (KYP) से जुड़े 77.3% लाभार्थी प्रवासन के लिए इच्छुक हैं, जो यह दर्शाता है कि यह योजना मुख्य रूप से युवाओं को बाहरी बाजारों में रोजगार तलाशने के लिए तैयार और प्रेरित कर रही है। इसके ठीक विपरीत, स्वरोजगार योजना (MMUY) के 76.0% लाभार्थी स्थानीय स्तर पर ही रोजगार करना पसंद करते हैं, जो इस बात का मजबूत प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर वित्तीय या उद्यमशीलता सहायता (स्वरोजगार) प्रवासन को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। वहीं, जिन लोगों ने किसी योजना का लाभ नहीं लिया है (गैर-लाभार्थी), उनमें भी प्रवासन की इच्छा (59.3%) अधिक है, लेकिन यह KYP लाभार्थियों की तुलना में कम है।

इन स्पष्ट अवलोकनों की सांख्यिकीय वैधता (Statistical Validity) को प्रमाणित करने के लिए काई-स्क्वायर परीक्षण (χ^2) किया गया। विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राप्त काई-स्क्वायर का मान 40.7 है। जब हम इसकी तुलना 2 स्वतंत्रता की कोटि (df = 2) और 5% सार्थकता स्तर ($\alpha = 0.05$) पर क्रिटिकल या सारणीबद्ध मान (5.991) से करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि गणना किया गया मान (40.7) क्रिटिकल मान से बहुत बड़ा है।

चूँकि $40.7 > 5.991$ है, इसलिए हम शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis - H_0) को मजबूती से खारिज (Reject) करते हैं।

सांख्यिकीय रूप से यह सिद्ध होता है कि 'योजना के प्रकार' और 'प्रवासन के व्यवहार' के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण (Highly Significant) संबंध है। योजनाएं तटस्थ (neutral) नहीं हैं; उनका व्यक्ति के करियर और स्थान के चुनाव पर सीधा असर पड़ता है। नीति-निर्माताओं (Policymakers) के लिए इस डेटा से एक स्पष्ट इनसाइट (Insight) यह मिलता है कि: यदि राज्य का उद्देश्य 'ब्रेन-ड्रेन' या श्रमिकों के प्रवासन को रोकना है, तो MMUY (स्वरोजगार) जैसी योजनाओं के फंड और पहुँच को बढ़ाना चाहिए। वहीं, KYP जैसी योजनाएं लोगों की गतिशीलता (Mobility) को बढ़ा रही हैं और उन्हें राज्य के बाहर के अवसरों के लिए सक्षम बना रही हैं।

5.3 प्रवासन के कारण (गुणात्मक विश्लेषण)

तालिका 3: प्रवासन के लिए प्रेरित करने वाले कारक (Ranked)

कारक	KYP लाभार्थी (%)	गैर-लाभार्थी (%)	कुल प्रतिक्रिया
बेहतर वेतन (Better Wages)	60%	75%	आर्थिक (Economic)
कौशल के अनुरूप नौकरी न मिलना (Job Mismatch)	85%	20%	संरचनात्मक (Structural)
शहरी जीवनशैली/प्रतिष्ठा (Aspirational)	40%	15%	सामाजिक (Social)
पासपोर्ट/विदेश जाने की इच्छा	30%	5%	वैश्विक (Global)

नोट: बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple response)

व्याख्या: KYP लाभार्थियों के लिए 'कौशल के अनुरूप नौकरी न मिलना' सबसे बड़ा कारक (85%) है। यह बांका जिले में 70% पासपोर्ट वृद्धि के पीछे के मुख्य कारण को स्पष्ट करता है। युवा अब केवल "पेट भरने" के लिए पलायन नहीं कर रहे हैं (जिसे 'Distress Migration' कहा जाता है), बल्कि वे अपने नए अर्जित कौशल का उपयोग करने के लिए पलायन कर रहे हैं (जिसे 'Aspirational Migration' कहा जाता है)।

6. चर्चा और विश्लेषण (Discussion and Analysis)

6.1 कौशल विकास का द्वंद्व: 'सशक्तिकरण' या 'निष्कासन'?

अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि कौशल विकास (Skilling) अपने आप में प्रवासन का हल नहीं है, बल्कि यह प्रवासन का एक 'सुगमकर्ता' (Facilitator) बन सकता है। हैरिस-टोडारो मॉडल के संदर्भ में, KYP प्रशिक्षण ने युवाओं की 'अपेक्षित आय' (Expected Income) को बढ़ा दिया है। चूंकि बांका की स्थानीय अर्थव्यवस्था (कृषि और सीमित पर्यटन) इस इच्छित आय को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए युवा 'आरक्षित मजदूरी' (Reservation Wage) से कम पर काम करने के बजाय पलायन करना पसंद करते हैं। यह स्थिति बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित इस तथ्य के अनुरूप है कि केवल 8.25% स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियों में कार्यरत हैं।

6.2 इच्छाशक्ति प्रवासन का उभार

बांका जिले में पासपोर्ट आवेदनों में 70% की वृद्धि एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह बताता है कि प्रवास की प्रवृत्ति बदल रही है। पहले बांका के श्रमिक पंजाब या हरियाणा के खेतों में काम करते थे। अब, KYP और उच्च शिक्षा (BSCC) प्राप्त युवा, खाड़ी देशों (Gulf Countries) या भारत के बड़े शहरों में सेवा क्षेत्र (Service Sector) की

नौकरियों - जैसे रिटेल, लॉजिस्टिक्स और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन - की खोज में जुटे हैं। इसे 'एस्पिरेशनल माइग्रेशन' कहा जा सकता है, जो गरीबी से नहीं, बल्कि बेहतर अवसरों की तलाश में आधारित है।

6.3 उद्यमिता: ठहराव का स्थायी आधार

इसके विपरीत, 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' (MMUY) ने ठहराव (Retention) के एक प्रभावी उपाय के रूप में कार्य किया है। जब सरकार युवाओं को 10 लाख रुपये का ऋण और अनुदान देती है, तो यह उन्हें स्थानीय बाजार में 'हितधारक' (Stakeholder) बना देती है। बांका के संदर्भ में, जिन युवाओं ने कृषि-प्रसंस्करण या छोटे विनिर्माण में निवेश किया, वे न केवल रुके, बल्कि उन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन (Value Addition) भी किया। यह निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

6.4 स्थानीय अवसंरचना और पर्यटन की भूमिका

बांका में ओढ़नी डैम और मंदार पर्वत का विकास पर्यटन क्षमता को दर्शाता है, लेकिन यह अभी भी रोजगार का प्राथमिक स्रोत नहीं बन पाया है। "न्यू एज इकोनॉमी" के तहत, यदि इन पर्यटन स्थलों के आसपास **सेवा क्लस्टर** (जैसे होटल प्रबंधन, गाइड, हस्तशिल्प बिक्री) विकसित किए जाएं, तो KYP प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही खपाया जा सकता है ।

7. नीतिगत निहितार्थ और सिफारिशें (Policy Implications and Recommendations)

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, बिहार सरकार और नीति निर्माताओं के लिए निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तावित हैं:

7.1 कौशल प्रशिक्षण का स्थानीयकरण (Localization of Skilling)

KYP के पाठ्यक्रम को 'सामान्य' (जेनेरिक) से 'स्थान-विशिष्ट' (Location-specific) में बदलने की आवश्यकता है।

सुझाव: बांका के लिए एक विशिष्ट KYP मॉड्यूल विकसित किया जाए जो रेशम बुनाई, समकालीन कृषि विधियों, और सौर ऊर्जा देखभाल (बांका में सौर संयंत्रों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए) पर आधारित हो। इससे 'कौशल बेमेल' में कमी आएगी।

7.2 उद्यमिता समूह का विकास

सिर्फ ऋण प्रदान करना पर्याप्त नहीं है; एक पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की आवश्यकता है।

उपाय: बांका के अमरपुर और कटोरिया ब्लॉक में 'ग्रामीण औद्योगिक पार्क' बनाए जाएं, जहां MMUY लाभार्थियों को बिजली, पानी और बाजार लिंकेज (Market Linkage) की सुविधा प्राप्त हो। यह 'क्लस्टर दृष्टिकोण' (Cluster Approach) प्रवासन को रोकने में व्यक्तिगत ऋण से ज्यादा प्रभावी सिद्ध होगा।

7.3 डिजिटल गिग अर्थव्यवस्था का समावेश

चूंकि KYP युवाओं को कंप्यूटर साक्षरता प्रदान कर रहा है, सरकार को 'डिजिटल प्रवासन' को प्रोत्साहित करना चाहिए- अर्थात्, कार्य डिजिटल तरीके से उपलब्ध हो, बजाय इसके कि युवा विदेश जाएं।

सुझाव: बांका में उच्च गति इंटरनेट वाले 'सह-कार्यस्थल' (Co-working Spaces) या 'ग्रामीण बीपीओ' (Rural BPOs) की स्थापना की जाए, जैसा कि बिहार की नई आईटी नीति और स्टार्टअप नीति में योजना बनाई गई है।

7.4 पासपोर्ट और सुरक्षित आव्रजन

चूंकि प्रवासन को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता और यह कुछ हद तक 'आकांक्षी' है, सरकार को इसे नियामित और सुरक्षित करना चाहिए।

सुझाव: बांका में एक 'प्रवासी सहायता केंद्र' (Migrant Support Centre) स्थापित किया जाए जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को सुरक्षित प्रवासन, कानूनी अधिकारों और वित्तीय साक्षरता की जानकारी प्रदान करे।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

इस शोध पत्र ने अनुभवात्मक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि बांका जिले में युवा शिक्षित लोगों के प्रवासन व्यवहार पर सरकारी योजनाओं का गहरा, किंतु विविध परिणाम है। काई-स्क्वायर परीक्षण (\chi^2 = 40.7) ने यह प्रमाणित किया है कि कौशल विकास (KYP) और प्रवासन के बीच एक सकारात्मक संबंध है, अर्थात कौशल प्राप्त करने के बाद प्रवासन की संभावना बढ़ जाती है। यह एक नकारात्मक परिणाम नहीं है, बल्कि यह युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं और क्षमताओं का संकेत है। दूसरी ओर, 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और प्रवासन के रोकथाम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

बांका का अनुभव यह सिखाता है कि 'कौशल' (Skill) और 'अवसर' (Opportunity) के बीच का फासला प्रवासन का प्रमुख कारण है। यदि बिहार सरकार अपनी 'न्यू एज इकोनॉमी' की अवधारणा को साकार करना चाहती है, तो उसे केवल मानव पूंजी के निर्माण (Skilling) पर नहीं, बल्कि उस पूंजी के स्थानीय उपयोग (Employment Generation) पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। बांका जिले में पासपोर्ट आवेदनों की वृद्धि को रोकने के बजाय, इसे 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) को 'ब्रेन सर्कुलेशन' (Brain Circulation) में बदलने की रणनीति अपनानी चाहिए, जहाँ प्रवासी युवा अपनी आय और कौशल को अपने गृह जिले में वापस निवेश करें। अंततः, "न्याय के साथ विकास" का असली मतलब युवाओं को 'पलायन की स्वतंत्रता' और 'रुकने का विकल्प' दोनों प्रदान करना है।

References:

- Government of Bihar. (2025). *Bihar Economic Survey 2024-25*. Finance Department, Government of Bihar.
- Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). (2024). *Periodic Labour Force Survey (PLFS) – Annual Report 2023-24*. Government of India.
- Bihar Skill Development Mission. (2024). *Impact assessment of Kushal Yuva Program (KYP) on youth employability*. Department of Labour Resources, Government of Bihar.
- NITI Aayog. (2024). *Best practices in social sector: A compendium of aspirational districts*. Government of India.
- Datta, A., Rodgers, G., Rodgers, J., & Singh, B. K. N. (2014). Contrasts in development in Bihar: A tale of two villages. *Journal of Development Studies*, *50*(9), 1197–1208. https://doi.org/10.1080/00220388.2014.925539
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. *The American Economic Review*, *60*(1), 126–142.
- IHD & ILO. (2024). *India employment report 2024: Youth employment, education and skills*. Institute for Human Development and International Labour Organization.
- Kumar, A., & Singh, R. (2021). Skill development and migration: A study of rural youth in Bihar. *Journal of Social and Economic Development*, *23*(2), 345–362.

- Rodgers, G., Mishra, S. K., & Sharma, A. N. (2016). Four decades of village studies and surveys in Bihar. In H. Himanshu, P. Jha, & G. Rodgers (Eds.), *The changing village in India: Insights from longitudinal research* (pp. 45–72). Oxford University Press.
- Sharma, A. N. (2005). Agrarian relations and socio-economic change in Bihar. *Economic and Political Weekly*, *40*(10), 960–972.
- Singh, D. K., & Kumar, P. (2022). Evaluation of Mukhyamantri Udyami Yojana in promoting entrepreneurship among marginalized communities in Bihar. *Indian Journal of Public Administration*, *68*(3), 412–428.
- Tiwari, C., Nandy, A., & Kundu, S. (2021). India's rural employment guarantee scheme – How does it influence seasonal rural out-migration decisions? *Journal of Policy Modeling*, *43*(6), 1234–1254. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.10.001
- Department of Industries, Bihar. (2024). *Mukhyamantri Udyami Yojana: Scheme guidelines and beneficiary statistics*. https://udyami.bihar.gov.in
- International Labour Organization. (2024). *Youth employment in India: Dimensions and challenges*. https://www.ilo.org/india